Foodgrain Export Policy

*246. DR. T. SUBBARAMI REDDY:†
SHRI VAYALAR RAVI:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are seriously considering to make export of foodgrains a "completely market-driven activity" by facilitating its export by private sector;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) whether Mid-Year Review of Economy released on November 14 the need to establish India as a reliable supplier in global grain market has been indicated; if so, the steps government are taking to enunciate stable export policy for foodgrains?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The EXIM policy allows export of foodgrains without any restrictions, by all exporters as per their commercial prudence. In order to promote and facilitate exports from the Central pool stocks, certain Post-delivery expenses to cover upgrading, fumigation, handling, etc., are allowed to the exporters. An Inter Ministerial High Level Committee of the FCI makes suitable recommendations to the Government in this regard.

(c) Yes, Sir. The Mid-Year Review of November, 2003 has highlighted this need. For this purpose, consultations have been initiated with the concerned stake holders.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, as the hon. Minister knows, in our country we have been producing foodgrains and some States are surplus and some States are deficit. The prices of foodgrains are totally flexible. In some States they are high and in some States they

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.

are low. This can be controlled by reducing the butter stocks by exporting and by controlling prices. We all know that farmers are committing suicides because they are not getting adequate prices. They are not able to meet their expenses and pay their debts. So, I would like to know from the Government how the Government is going to improve the export policy. In the reply he has referred to private participation. The export policy allows privatisation. But that is not sufficient. What efforts the Government is making to improve the exports of foodgrains? Are you going to make any special policy thereby giving incentives, in such a way that buffer stocks are reduced and, in future the prices are controlled so that the farmers are benefited?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सुब्बारामी रेड्डी जी ठीक पूछ रहे हैं। हमारे पास 630 लाख टन फूडग्रेन था। आप जो उसी मशविरे से यानी पिछले ढाई-तीन साल में काफी बड़े पैमाने पर एक साइजेबिल और दुनिया के तकरीबन 70-80 देश हैं जिनके बाजार में जाकर हमने एक्सपोर्ट किया है। उसके पीछे जो आप बात कह रहे हैं वही भावना है, यहां का जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल सैक्टर है वह मजबूत रहते हुये हमने 2000.2001 मे 20 लाख टन अनाज एक्सपोर्ट किया था, 2001-2002 में 63 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया था और 2002-2003 में 148 लाख टन एक्सपोर्ट किया था। तीनों सालों का लगभग मिलाकर के 310 लाख मीट्रिक टन अनाज एक्सपोर्ट किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के बाजार में हमारी जगह बनी हुई है। हमारी जो योजना है, जो पॉलिसी है, उसको बनाने में हम लगे हुये हैं। जो पॉलिसी है, उसके लिए एक नीति बने। जो डोमेस्टिक है, जो खाद्य सुरक्षा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। उस खाद्य सुरक्षा को देखते हुए हमारे पास जो अनाज है, उससे दुनिया के बाजार में जो हमारी जगह बनी है उस जगह को बनाये रखने के लिए हम नीति को पूरी तरह से, अभी तक तो एडहाक लेवल पर हम सब काम ठीक से करते रहे हैं, लेकिन अब हमारी योजना है कि एक व्यवस्थित नीति बनाकर के आयें। निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि दुनिया के बाजार में जो हमारी.....।

श्री सभापति: आप यहां नीति बनाकर के आ जाइये।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, my second supplementary is, as per some newspaper reports, the Food Corporation of India has raised the prices of paddy and grains exported by the exporters. They have raised the prices and delayed the fixing of rates. They need 45 days to procure from the Food Corporation of India. As a result of this, the exports have come to a standstill. How are you going to solve this problem?

श्री शरद यादव: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हर तीन महीने में जो प्राइसिज़ हैं, उनके बारे में एचएलसी बनी हुई है, हाई लैबल कमेटी बनी हुई है जिसमें एक हमारा विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं और फाइनेंस के लोग हैं। वे सब तीन महीने बाद बाजार को देखकर और दुनिया के बाजार को देखकर अपनी कीमतें तय करते रहते हैं। इस आधे क्वार्टर के लिए जो कीमतें हमने अनाउंस की हैं, वह गेहूं के लिए हैं छः हजार.....

श्री सभापति: वह तो लोगों ने अखबारों में पढ़ ली हैं।

श्री शरद यादव: राइस के लिए 7600 है।

SHRI VAYALAR RAVI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has rightly said that the food security is their main concern. The food security can be ensured only if there is sufficient production. And, the food production has gone up to 203 million tonnes, but it is not going further because of the cost of production going up every time because of the fertilizer price and the costly irrigation facilities due to high electricity prices. In this background, may I know from the hon. Minister, what would be the priority? Is your priority the food security or the exports? With the background of people dying because of starvation and suicides, will you consider priority to be given to food security over exports?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, वे दोनों ही बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो डोमैस्टिक नीड है, जो फूड सिक्योरिटी है, वह सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद जो सरप्लस हमारे पास फूड ग्रेन है, उस फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करने की नीति हम बनाए हुए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी देश के अंदर खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना है।

डा॰ नारायण सिंह मानकलाव: माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ग्वार और जीरे का जो भाव लगातार जा रहा है, उसका एक्सपोर्ट करने की कोई योजना भारत सरकार बना रही है?

श्री शरद यादव: महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे संज्ञान में जो बात लायी है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो एक्सपोर्ट गेहूं और चावल का होता है, बासमती का होता है और चीजों का भी होता है लेकिन उन्होंने जो बात कही है, मैं उसको दिखवा लेता हूं यह काम कॉमर्स मिनिस्टरी करती है, इसलिए उनके पास मैं सूचना पहुंचा दूंगा।